औद्योगिक नीतियों एवं योजनाओं के तहत उद्यमियों को प्रोत्साहन एवं लेटर्स ऑफ कम्फर्ट का वितरण

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक वर्ष की रिकॉर्ड अवधि में 10,715 करोड़ रुपये के 28 औद्योगिक इकाई निवेश प्रस्तावों को लेटर ऑफ कम्फर्ट- (एलओसी) प्रमाण पत्र का वितरण

अशोक लीलैंड, वरुण बेवरेजेज, बनासकांठा डेयरी (अमूल), एशियन पेंट्स, कजरिया सेरामिक्स, सी पी मिल्क एवं खाद्य उत्पाद जैसे निवेशकों को हजारों रोजगार का सृजन करने हेतु एलओसी प्रदान किए गए

32 औद्योगिक इकाइयों को 1333.05 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ

डबल इंजन सरकार ने असंभव को संभव में परिवर्तित कर दिया: मा. मुख्यमंत्री

उद्योग तथा संस्थान को जोड़ने से कौशल विकास हेतु एक उत्कृष्ट मंच निर्मित होता है : माननीय मुख्यमंत्री

लखनऊ, 30 अगस्त 2024: माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास एवं विकास के प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक नीतियों एवं योजनाओं के तहत उद्यमियों को प्रोत्साहन राशि वितरित की गईं। इस कार्यक्रम में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश पॉलिसी तथा एफ़डीआई पॉलिसी 2023 के तहत 10 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) भी वितरित किए गए। समग्र रूप से कुल 28 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रमाणपत्र प्रदान किए गए जो ₹10,715 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का दर्शाते हैं। इनमें से 10 एलओसी प्रमाणपत्र, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रदान किए गए। यह महत्वपूर्ण कदम राज्य की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने तथा औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देने हेतु एक सहायक वातावरण प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कार्यक्रम के दौरान, माननीय मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन वितरित किए, जैसे औद्योगिक निवेश संवर्धन योजना (IIPS) 2003 तथा 2012 नीति के तहत 7 औद्योगिक कंपनियों को 66.66 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन राशि मिली, जबकि IIPS 2012 नीति के तहत पार्ले एग्रो, बिड़ला कॉरपोरेशन, मंगलम सीमेंट, एवं वृंदावन एग्रो सहित दस औद्योगिक इकाइयों को 98.25 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई। इन दोनों नीतियों के तहत कुल मिलाकर 17 औद्योगिक इकाइयों को 164.91 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि निर्गत की गयी, जिसमें प्रमुख लाभार्थियों में सी पी मिल्क, ओमैक्स ऑटो लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट, सुयश पेपर मिल, बिड़ला कॉरपोरेशन लिमिटेड, वरुण बेवरेजेज, ईकोप्लस स्टील प्रा. लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट एवं जिंदल शॉ लिमिटेड शामिल हैं।

इन 28 प्रस्तावों में से कुल 4,153 करोड़ रुपये के 10 निवेश प्रस्ताव बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्रों में हैं, जहाँ राज्य सरकार इन क्षेत्रों के व्यापक विकास हेतु निवेश प्रस्तावों को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अतिरिक्त, कुल 3,714 करोड़ रुपये के 12 निवेश प्रस्ताव पश्चिमी क्षेत्र में हैं, और कुल 2,847 करोड़ रुपये के 6 निवेश प्रस्ताव मध्य क्षेत्र में हैं।

आईटी एवं आईटीईएस नीति-2022 के तहत, सैमसंग, लावा, एवं HCL सहित पांच इकाइयों को 212.63 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। इसके अतिरिक्त, अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति-2012 और 2017 (मेगा) के तहत, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग और जेके सीमेंट सहित 935.51 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया गया तथा एक अन्य इकाई को वन-टाइम पुनर्वास नीति-2015 के तहत 20 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

कार्यक्रम में निवेशकों को संबोधित करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश अराजकता, अव्यवस्था और अपराध के लिए जाना जाता था, जो पिछली सरकार की दूरदृष्टि की कमी का परिणाम था। आज, कानून के शासन के साथ, राज्य एक प्रमुख निवेश गंतव्य बन गया है। फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से राज्य ने ₹40 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए, जिसमें से ₹10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक समारोह के माध्यम से जमीन पर उतारा गया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि माननीय प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य ने 27 सेक्टोरल नीतियां लागू की हैं और उद्यमियों की सहायता के लिए 125 उद्यमी मित्रों की तैनाती की है। सरकार, अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टालरेंस की नीति को प्रदर्शित करती है जिससे निवेशक की पूंजी सुरक्षित हुयी है। सरकार झांसी और कानपुर के बीच एक नए औद्योगिक शहर, बीडा और जेवर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री, योगी आदित्नाथ ने लखनऊ के आसपास एक राज्य राजधानी क्षेत्र की घोषणा भी की, जिससे सभी जनपदों में बिजली की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अब विकास का इंजन बन गया है, जो भारत के विकास में योगदान दे रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के विजन “विकसित भारत 2047” को साकार कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यदि उद्योग और संस्थान हाथ मिलाते हैं तो कौशल विकास के लिए एक उत्कृष्ट मंच तैयार होता है। उन्होंने उद्यमियों को कुशल जनशक्ति के लिए इन संबंधों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

यह उल्लेखित किया गया कि एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों की निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत भी हमने अशोक लीलैंड को 1 एलओसी स्वीकृत की है, जो 186 करोड़ रुपये के निवेश से लखनऊ में एक वाणिज्यिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए फॉर्च्यून इंडिया 500 सूचीबद्ध कंपनी है। साथ ही, राज्य सरकार ने इस नीति के तहत दो एफडीआई परियोजनाओं (जापान, यूएसए) और दो-फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों को 4 फ्रंट एंड भूमि सब्सिडी स्वीकृत की है। इसके फलस्वरूप राज्य सरकार 760 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने में सक्षम रही है, जबकि लगभग 2700 करोड़ रुपये निवेश के आवेदन पाइपलाइन में हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन और एनआरआई मंत्री, यूपी सरकार श्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' जी ने कहा कि यूपी का प्रगति के पथ पर यात्रा अभी आरंभ हुई है। पिछले सात वर्षों में किए गए प्रयासों का लाभ मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे, जलमार्ग, फ्रेट कॉरिडोर और औद्योगिक पार्क शामिल हैं, जिससे व्यापार करने में आसानी होती है।

पूर्व में, माननीय मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह तथा माननीय औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन एवं एनआरआई मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार श्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' जी ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक वीडियो प्रस्तुति में गत 1-2 वर्षों में राज्य भर में विभिन्न विनिर्माण एवं प्रसंस्करण सुविधाओं का आरंभ प्रदर्शित किया गया। वीडियो में उत्तर प्रदेश द्वारा अपने औद्योगिक बुनियादी ढांचे की वृद्धि में प्राप्त महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला गया, जिससे घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेश आकर्षित हुए। औद्योगिक प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने पर राज्य का ध्यान स्पष्ट था, जो भारत के औद्योगिक परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इसके उद्भव को रेखांकित करता है।

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले पांच प्रतिष्ठित उद्यमियों के साथ अनुभव साझा करने का सत्र भी आयोजित किया गया। श्री जे.बी. पार्क, अध्यक्ष - दक्षिण एशिया, सैमसंग ने उत्तर प्रदेश में सैमसंग की यात्रा और उन अनुकूल नीतियों के विषय में बात की, जिन्होंने क्षेत्र में उनके संचालन एवं विस्तार को सुविधाजनक बनाया है। उन्होंने कहा, "नोएडा यूनिट दुनिया के लिए 'मेक इन इंडिया' के लिए प्रतिबद्ध है और सैमसंग उत्तर प्रदेश और राज्य की जनता के साथ सह-समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अत्याधुनिक तकनीक प्रस्तुत करना और स्थानीयकरण में वृद्धि निरंतर जारी रखेंगे। साथ ही, हम अपने सीएसआर के रूप में कौशल के माध्यम से यूपी के युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करने में सहायता करेंगे।

जेके सीमेंट के प्रबंध निदेशक श्री राघवपत सिंघानिया ने कंपनी के विकास पथ और राज्य की औद्योगिक नीतियों के तहत प्राप्त समर्थन के विषय में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सीएम की टीम परियोजनाओं की प्रगति के विषय में निवेशकों से चर्चा करती है।

आरसीसीपीएल (बिरला कॉरपोरेशन) के एमडी तथा सीईओ श्री संदीप घोष ने राज्य के सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और सक्रिय शासन का उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश में निवेश के लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने हवाला दिया कि 'यूपी सरकार वचनबद्धता का ध्यान रखती है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है।'

गैलेंट इस्पात के अध्यक्ष श्री सी.पी. अग्रवाल ने अनुकूल कारोबारी माहौल एवं औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने वाले प्रोत्साहनों पर विचार साझा किये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के अपराध एवं संगठित अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता के रवैये ने निवेश के द्वारा खोल दिये हैं।

एचसीएल समूह के सीएफओ एवं अध्यक्ष श्री पवन दानवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश की नीतिगत रूपरेखा उत्कृष्ट है तथा गत 8 वर्षों में इसका कार्यान्वयन निर्बाध रहा है। "यूपी एचसीएल का घर है, हमारी कंपनी राज्य में 4200 करोड़ का निवेश करेगी"

अशोक लीलैंड के प्रबंध निदेशक श्री शेनु अग्रवाल ने नवाचार और प्रौद्योगिकी पर राज्य के फोकस पर जोर दिया, जो नए निवेश को आकर्षित करने और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा है और उत्तर प्रदेश में सबसे प्रगतिशील, सहायक सरकार है।

कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', राज्य मंत्री जसवन्त सिंह सैनी, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री अजीत पाल, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर, निवेशक एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का समापन लाभार्थी इकाइयों के उद्यमियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री की एक ग्रुप फोटो सेशन के साथ हुआ। यह प्रतीकात्मक इशारा उत्तर प्रदेश में सरकार तथा औद्योगिक क्षेत्र के मध्य सहयोगात्मक भावना को रेखांकित करता है, जो सतत आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता को उजागर करता है।